POSTAL REG.NO. RJ/JPC/M-28/2009-11 (RNI. REG. NO. 39658/83) # ग्रा.ग./2011/अंक 05 कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 मई, सी.एस.ओ., आरएमएस गांधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 मई, 2011 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! देश के शासकों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की इच्छाशक्ति होती तो देश में इतना भ्रष्टाचार नहीं पनपता। और, यदि ऐसा होता तो आज हम विकसित देशों की गिनती में पहले पायदान पर होते। क्योंकि, हमारा देश संसाधनों के मामले में अव्वल है। यह मानना है 'ग्राम गदर' के पाठक भंवर लाल छीपा का।

देश को आजाद हुए 64 साल हो रहे हैं। लेकिन हमारा जमीनी स्तर पर जनतंत्र अभी भी इतना परिपक्व नहीं हो पाया, जो राजनेताओं को सही सीख दे सके। छीपा का कहना है, अब गांधीवादी अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जन-जन को जगाया है। इससे आम लोगों का भ्रष्टाचार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश उभर कर सामने आया।

इसका परिणाम भी सामने आया। सरकार ने समय रहते जनता की भागीदारी में लोकपाल कानून बनाने की बात मान ली। यह जनता की जीत है और जनतंत्र के परिपक्व होने की दिशा में बढ़ा एक आशावादी कदम है।

अब कुछ राजनेता अन्ना हजारे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। वह चाहते हैं कि जनता राजनेताओं पर उंगली न उठाएं, इससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस लगती है। उनका कहना है लोकपाल कानून से कुछ नहीं होने वाला? जैसे सब कुछ उनकी ही मुट्ठी में बन्द है। जबकि एक दिन चुने गए भ्रष्ट और अपराधी छवि के राजनेता को वापस बुलाने का अधिकार भी जनता को मिल कर रहेगा।

कानूनी जानकारी

अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा चाहते हैं, तो वसीयत जरूर लिखें !

गांवों में कम पढ़े-लिखे लोग वसीयत लिखना नहीं जानते। वसीयत का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी सम्पत्ति के बटवारे के बारे में अपनी इच्छा की लिखित, कानूनी व वैधानिक घोषणा करना। हर पुरूष व महिला को अपनी इच्छा के मुताबिक वसीयत करने व लिखने का अधिकार कानून में दिया गया है।

- वसीयत खुद लिखी जा सकती है या अनपढ़ होने पर किसी विश्वासपात्र व्यक्ति से लिखवाई जा सकती है। लिखवाने के बाद उसे ध्यान से दुबारा पढ़ाकर सुनना चाहिए। इसके बाद अपने हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी करनी चाहिए। वसीयत सादा कागज पर भी लिखी जा सकती है। वसीयत लिखने व लिखाने वाला व्यक्ति स्वस्थ्य चित्त होना चाहिए।
- वसीयत पूरी तरह से लिखाने के बाद उस पर दो जानकार व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराने चाहिए। वसीयत का सुरक्षा की दृष्टि से पंजीयन भी करा सकते हैं। वसीयत करने वाला व्यक्ति जब चाहे अपनी वसीयत को परिवर्तित भी कर सकता है। वसीयत करते समय यह खास तौर से ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी सम्पत्ति सही लोगों के पास जा रही है।
- यदि वसीयत नहीं की गई हो, तो ऐसी सम्पत्ति पर उस व्यक्ति के लड़के-लड़कियों को बराबर सम्पत्ति प्राप्त करने का हक कानून में दिया गया है। पुराने कानून में लड़कियों का सम्पत्ति में हिस्सा नहीं था, लेकिन अब उन्हें सम्पत्ति में बराबर की सम्पत्ति प्राप्त करने का हक दिया गया है।

उपभोक्ता फैसले

बिना रसीद रोडवेज ने बसूला लगेज शुल्क

रोडवेज की जयपुर-दिल्ली डीलक्स बस से जी.एल.अग्रवाल ने अक्टूबर, 2008 में यात्रा की थी। उनसे बस की डिक्की में सामान रखने के लिए बस परिचालक ने प्रति नग दो रुपए शुल्क मांगा। उन्होंने मांगा गया शुल्क परिचालक को दे दिया, लेकिन उन्हें इसकी रसीद नहीं दी गई। उन्होंने बुकिंग क्लर्क से बात की तो जवाब मिला 1995 से 2 रुपए प्रति नग लेने के आदेश हैं, जिसकी रसीद भी मिलती है।

उन्होंने दिल्ली उपभोक्ता मंच में रोडवेज के खिलाफ परिवाद दायर कर पूरी स्थिति बताई। सुनवाई पर रोडवेज की ओर से यह नहीं बताया जा सका कि 15 साल पहले जारी उक्त आदेश से आज तक कितना लगेज शुल्क जमा हुआ। उपभोक्ता मंच ने यह भी पाया कि रोडवेज द्वारा काटे गए टिकट पर यात्रा के पूरे विवरण के साथ किराया राशि का इंद्राज नहीं था।

उपभोक्ता मंच ने इन अनियमिताओं को गंभीर मानते हुए रोडवेज को आदेश दिया है कि वह एक लाख रुपए राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में हर्जाने स्वरूप जमा कराए। साथ ही, परिवादी जी.एल. अग्रवाल को क्षतिपूर्ति के रूप में 10 हजार रुपए अदा करने के निर्देश भी दिए हैं।

'ग्राम गदर' पत्रकारिता पुरस्कारों की घोषणा

ग्रामीण पत्रकारिता को बढ़ावा देने की दृष्टि से वर्ष 2002 से आरम्भ 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार प्रति वर्ष 13 अप्रेल के दिन घोषित किए जाते हैं। ये पुरस्कार उन श्रेष्ठ पत्रकारों को दिये जाते हैं, जिन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से जनहित के मामलों को असरदार तरीके से उठाया है। ये पत्रकार चाहे स्वतन्त्र रूप से पत्रकारिता करते हों, या फिर किसी समाचार पत्र से जुड़े हुए हो सकते हैं।

प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी वर्ष 2010 में उल्लेखनीय लेखन प्रकाशित करने वाले पत्रकारों से 'भ्रष्टाचार' विषय पर प्रविष्ठियां आमन्त्रित की गई थीं।

प्राप्त प्रविष्ठियों में से श्रेष्ठ चयन के लिए ख्यातिप्राप्त वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र बोड़ा की अगुवाई में निर्णायक मंडल का गठन किया गया। निर्णायक मंडल द्वारा आम सहमति से भीलवाड़ा जिले के स्वतंत्र पत्रकार लक्ष्मी लाल (लखन सालवी) को वर्ष 2010 के लिए 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है। श्री सालवी को दस हजार रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा।। पुरस्कार का वितरण बाद में उचित समय पर किया जाएगा।

लखन सालवी भीलवाड़ा जिले के मूल निवासी हैं तथा दैनिक भास्कर, निराला राष्ट्रध्वज, विविधा फीचर्स, तथ्य भारती, डायमंड इंडिया आदि अनेक छोटे बड़े पत्र-पत्रिकाओं के लिए अपने लेख लिखते हैं, जो कि जनहित के मुद्दों से सीधे जुड़े हुए होते हैं।

डकार जाते हैं गरीबों का राशन

खाद्य मंत्री बाबूलाल नागर ने प्रदेश की राशन वितरण प्रणाली में भारी गड़बड़ी होने की बात स्वीकारी है। उन्होंने कहा कि राशन डीलर साल में तीन महीने का राशन खुद डकार जाते हैं और जनता को सिर्फ नौ महीने का राशन मिल पाता है। इस गड़बड़ी में राशन डीलरों के साथ-साथ कुछ सरकारी नुमाइन्दे भी शामिल होते हैं।

उन्होंने बताया कि राशन वितरण को बेहतर और गड़बड़ी रहित बनाने के लिए हाल ही जिला और तहसील स्तर पर सतर्कता समिति और आंवटन सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

इन समितियों में स्थानीय नागरिकों को भी शामिल किया गया है। इन्हें कभी भी राशन की दुकानों के निरीक्षण का अधिकार होगा। समिति सदस्य सरकारी नुमाइन्दों व डीलरों के खिलाफ पुख्ता सबूत होने पर कानूनी कार्रवाई तक कर सकते हैं।

रेतीले धोरों में सूरज से बिजली

उत्तर पश्चिमी राजस्थान के रेतीले धोरों में सूरज की रोशनी से बड़ी मात्रा में बिजली पैदा होगी। प्रदेश के झुंझुनूं से लेकर जैसलमेर जिले तक के क्षेत्र में स्पेशल सोलर एनर्जी जोन विकसित होगा। तीन सालों के दरम्यान इस क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर कुल 594 मेगावाट की सौर ऊर्जा से बिजली बनाने की कई इकाइयां स्थापित होंगी।

इस सोजर जोन में पूरा जैसलमेर व बीकानेर जिला, नागौर का खिंवसर और जोधपुर का फलौदी क्षेत्र भी शामिल है। इतनी बड़ी मात्रा में बिजली पैदा होने से प्रदेश बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा।

यहां पर सोलर थर्मल पावर की आठ इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जिनमें पांच बड़ी इकाइयां होंगी। इन इकाइयों से 430 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा।

महिलाएं एक साथ करें सफर तो फायदा

रोडवेज बसों में यदि पांच महिलाएं एक साथ सफर करें तो उन्हें 25 फीसदी रियायत मिलेगी। यह छूट अप्रेल से लागू हो गई है। महिलाओं द्वारा समूह में यात्रा के लिए आरक्षण चाहने पर सीट आरक्षण की व्यवस्था भी है।

राज्य सरकार का मानना है कि रोजाना हजारों महिलाएं सरकारी या निजी नौकरी अथवा दैनिक मजदूरी आदि के लिए जाने-आने के लिए रोडवेज बसों में यात्रा करती हैं। समूह में यात्रा करने पर इन्हें द्रुतगामी और साधारण बसों के यात्री किराए में 25 फीसदी रियायत मिलेगी। यह सुविधा राज्य में संचालित बसों में ही मिलेगी।

निजी स्कूलों में मुफ्त पढ़ेंगे गरीब बच्चे

नए शिक्षा सत्र से सभी निजी और अनुदानित स्कूलों को 25 फीसदी सीटों पर गरीब बच्चों को दाखिला देना होगा। इन बच्चों से ये स्कूल किसी तरह की फीस भी नहीं वसूलेंगे।

राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में यह व्यवस्था दी गई है। इस कानून को सख्ती से लागू कराने के लिए राज्य सरकार कई कदम उठा रही है। शिक्षा मंत्री मास्टर भंवरलाल ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि यदि निजी स्कूल इसकी पालना नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

महिला साक्षरता में पिछड़ा राजस्थान

राज्य सरकार ने पिछले दस सालों में महिला साक्षरता बढ़ाने के नाम पर 7 हजार 600 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इसके बावजूद इस अवधि में महिला साक्षरता में केवल पौने नौ फीसदी ही इजाफा हुआ है। जबकि, बिहार और झारखंड जैसे पिछड़े माने जाने वाले राज्यों में महिला शिक्षा का स्तर इस अवधि में क्रमशः 20 व 17 फीसदी बढ़ा है। यह राजस्थान की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा है। यह ही नहीं, महिला शिक्षा के मामले में राज्य पूरे देश में भी फिसड्डी है।

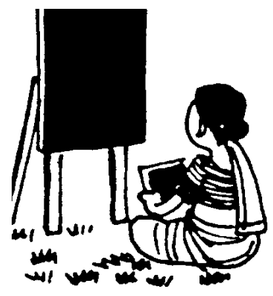

राज्य में जनगणना 2011 के नतीजों ने सरकारी कागजी दावों की पोल खोलते हुए इस सच्चाई को उजागर किया है। प्रदेश में इतना भारी भरकम खर्च करने के बावजूद महिला शिक्षा में खास इजाफा नहीं होना कई सवाल खडे करता है।

किसानों को चार प्रतिशत ब्याज पर ऋण

इस साल भी छोटे और सीमान्त किसानों को फसली ऋण की ब्याज दर 7 प्रतिशत जारी रखी गई है। समय पर ऋण वापसी करने वालों के लिए पिछले साल 2 प्रतिशत छूट दी गई थी। इससे समय पर ऋण वापसी करने वाले किसानों को 5 प्रतिशत ही ब्याज देना पड़ता था।

इस साल इस छूट को बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे समय पर ऋण चुकारा करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत ही ब्याज देना होगा। केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को ऋण देने की गति तेज करने के लिए बैंकों को निर्देश दिए गए हैं।

बाल विवाहों पर होगी कानूनी कार्रवाई

प्रदेशभर में बाल विवाह नहीं हों, इसकी पूरी निगरानी और प्रभावी रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों और एसपी को जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार की ओर से भेजे पत्र में निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में बाल विवाह रोकने के लिए समुचित कार्रवाई करें, साथ ही सूचना प्राप्त होने पर बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई करें।

पत्र में सभी कलेक्टरों, एसपी और डीएसओ कार्यालयों में कंट्रोल रूम स्थापित करने व 24 घंटे कियाशील रहने की व्यवस्था सुनिचित करने के भी निर्देश हैं। पत्र में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि किसी क्षेत्र में बाल विवाह होने पर अधिनियम के तहत उस क्षेत्र में नियुक्त बाल विवाह प्रतिबंध अधिकारियों (एसडीओ) की जवाबदेही और जिम्मेदारी होगी।

अब हम हुए 121 करोड़

भारत की जनगणना CENSUS OF INDIA 2011

अब भारत की जनसंख्या 121 करोड़ हो गई है। देश में 62 करोड़ 37 लाख पुरुष और 58 करोड़ 65 लाख महिलाएं हैं। जनगणना 2011 के मुताबिक पिछले 10 वर्षो में पूरे देश में पढ़े-लिखे लोगों की संख्या में उत्साहजनक वृद्धि हुई है। देश में अब 74 फीसदी लोग पढ़े-लिखे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश की जनसंख्या वृद्धि दर में भी कमी आना शुरू हो गया है।

राजस्थान में 2001 में कुल आबादी 5 करोड़ 65 लाख थी, वह अब बढ़कर 6 करोड़ 86 लाख हो गई है। इसमें 3 करोड़ 56 लाख पुरुष और 3 करोड़ 30 लाख महिलाएं हैं।

आपकी चिट्ठी मिली

आम लोगों तक आधारभूत सुविधाओं की पहुंच को ध्यान में रख कर आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जाता है। इनमें पानी, बिजली, सड़क, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास सेवाएं खासतौर से शामिल है। केन्द्र व राज्य सरकारें इन आधारभूत सुविधाओं के लिए हर साल बजट में करोड़ों रुपए का प्रावधान करती है। लेकिन सरकार के कागजों और व्यवहारिक रूप में बहुत बड़ा अन्तर रहता है।

जनकल्याण की जो भावना बजट के समय दिखाई पड़ती है वह आम जन के लिए मात्र एक सपना बन कर रह जाती है। क्योंकि सरकारी नौकरशाही घोषणाओं पर समयबद्ध रूप से अमल नहीं करती। सरकारी सेवाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण आवंटित बजट का काफी हिस्सा बीच में ही हजम हो जाता है। इससे जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों की जनता में विश्वसनीयता घटती जा रही है।

-लक्ष्मण सिंह, ब्यावर

देश में जिस तेजी से भ्रष्टाचार बढ़ा है उससे लोगों का लोकतंत्र से विश्वास डगमगाने लगा है। सबसे ज्यादा चिंताजनक तो यह है कि जनता के विश्वास पर चुने गए कई जनप्रतिनिधि खरे नहीं उतरते। राजनीतिक दलों के कई नेता भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे नजर आते हैं। पिछले साल के अन्त में एकसाथ सामने आए कई घोटाले इसे प्रमाणित करते हैं। आम जन इस कदर व्याप्त भ्रष्टाचार से पीड़ित ही नहीं बल्कि आक्रोशित भी है।

यह हाल ही भ्रष्टाचार के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे द्वारा जनहित में शुरू किए गए आन्दोलन के दौरान उभरकर सामने आया। वह तो केन्द्र सरकार समय रहते समझ गई व लोकपाल बिल के लिए उनकी सभी मांगों को मान लिया। वरना, देश का युवा वर्ग तो भ्रष्टाचार के खिलाफ 'हल्ला बोलने' को तैयार बैठा है।

-भंवर लाल छीपा, सांगानेर, जयपुर

कम्पोजिंग एवं लेआउट **राजकुमार त्रिवेदी**, 'कट्स' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485